भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2767
उत्तर देने की तारीख-12/08/2026

पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना का प्रभावी कार्यान्वयन

2767 #**श्री तेजवीर सिंह:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना के प्रारंभ होने के पश्चात प्राप्त, स्वीकृत, अस्वीकृत तथा लंबित शिक्षा ऋण आवेदनों की संख्या तथा स्वीकृत एवं वास्तव में संवितरित ऋण राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) इस योजना के अंतर्गत 3 प्रतिशत ब्याज उपादान से अब तक कितने विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं तथा इस मद के अंतर्गत कुल कितनी राशि संवितरित की गई है; और
(ग) इस योजना से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कितने विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): भारत सरकार ने नवंबर 2024 में केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना पीएम-विद्यालक्ष्मी शुरू की है। इस योजना के तहत, उन सभी छात्रों को संपार्श्विक-मुक्त और गारंटर-मुक्त शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है जो उच्च गुणवत्ता वाले उच्चतर शिक्षा संस्थानों (क्यूएचईआई) में योग्यता-आधारित प्रवेश प्राप्त करते हैं और जो शिक्षा ऋण प्राप्त करना चाहते हैं। इसके अलावा, 8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए, इस योजना के तहत अधिस्थगन अवधि यानी पाठ्यक्रम अवधि और एक वर्ष के दौरान 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 3 प्रतिशत ब्याज छूट प्रदान की जाती है। प्रत्येक वर्ष एक लाख तक नए छात्र जो किसी अन्य छात्रवृत्ति या शिक्षा ऋण पर ब्याज अनुदान का लाभ नहीं उठा रहे हैं, वे इस ब्याज छूट लाभ के लिए पात्र हैं। इस अवधि के दौरान 7 लाख नए छात्रों के लिए 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान लाभ प्रदान करने के लिए वर्ष 2024-25 से वर्ष 2030-31 तक 3,600 करोड़ रुपये का परिव्यय किया गया है।

इसके अलावा, उच्चतर शिक्षा विभाग प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (पीएम-यूएसपी) योजना का कार्यान्वयन कर रहा है जिसमें छात्रवृत्ति योजनाएं नामतः (i) कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के

लिए पीएम-यूएसपी केंद्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति योजना; तथा (ii) जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए पीएम-यूएसपी विशेष छात्रवृत्ति योजना; तथा योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से संबंधित पात्र छात्रों को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु पीएम-यूएसपी केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना (सीएसआईएस) शामिल हैं।

पीएम-यूएसपी केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना (सीएसआईएस) घटक के तहत, ऋण अधिस्थगन अवधि के दौरान भारत में तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को अपनाने के लिए 10 लाख रुपये तक की ऋण राशि पर पूर्ण ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। जिन छात्रों की वार्षिक सकल माता-पिता/पारिवारिक आय ₹4.5 लाख तक है, वे इस योजना के तहत पात्र हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, पीएम-यूएसपी सीएसआईएस के तहत, 892.81 करोड़ रुपये की राशि के 414,844 पूर्ण ब्याज सब्सिडी दावे प्राप्त हुए। पीएम-यूएसपी सीएसआईएस को पीएम-विद्यालक्ष्मी पोर्टल और पीएम-विद्यालक्ष्मी डिजिटल रुपी वॉलेट के माध्यम से भी प्रशासित किया जा रहा है।

6 नवंबर, 2024 को इस योजना के शुभारंभ के बाद से 3 अगस्त, 2026 तक 190,579 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 119,641 संपार्श्विक-मुक्त और गारंटर-मुक्त पीएम विद्यालक्ष्मी शिक्षा ऋण स्वीकृत किए गए हैं। स्वीकृत राशि 16,488.71 करोड़ रुपये है। ये 5 वर्ष तक की अवधि के लिए हैं। शिक्षा ऋण आमतौर पर शैक्षिक संस्थान द्वारा निर्धारित सेमेस्टर या वर्ष-वार शुल्क अनुसूची और अन्य आवश्यकताओं के आधार पर किश्तों में वितरित किए जाते हैं। इसलिए, 106,906 ऋणों के लिए 4478.96 करोड़ रुपये जो स्वीकृत राशि का 27.16 प्रतिशत है, वितरित किए गए हैं। किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए ब्याज सहायता के वार्षिक दावे अगले वित्तीय वर्ष में प्राप्त होते हैं।

6 नवंबर, 2024 से 31 मार्च 2025 के दौरान कुल 16,469 व्यक्तियों को पीएम विद्यालक्ष्मी शिक्षा ऋण प्राप्त हुआ। इनमें से कुल 5534 आवेदक ब्याज अनुदान से लाभान्वित हुए (4816 लोगों को 100 प्रतिशत ब्याज छूट का लाभ मिला, क्योंकि उनके परिवार की आय 4.5 लाख रुपये से कम है और 718 लोगों को 3 प्रतिशत ब्याज छूट का लाभ हुआ, क्योंकि उनके परिवार की आय 8 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है)।

अनुलग्नक-III जो 8 लाख रुपये वार्षिक आय श्रेणी के भीतर थे, वे 1.81 करोड़ रुपये की राशि के ब्याज अनुदान के लिए पात्र थे। इनमें से 4816 दावे पूर्ण ब्याज छूट से संबंधित थे और 718 दावे 3% ब्याज छूट घटक से संबंधित थे।

प्राप्त, स्वीकृत, वितरित, अस्वीकृत और लंबित पीएम-विद्यालक्ष्मी शिक्षा ऋण आवेदनों का राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक-I में है। इस योजना से लाभान्वित होने वाले अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के छात्रों की संख्या अनुलग्नक-II में दी गई है। संपार्श्विक मुक्त और गारंटर-मुक्त शिक्षा ऋण का प्रावधान मांग आधारित है और ऐसे ऋणों की संख्या की कोई ऊपरी सीमा नहीं है।

सरकार योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए पात्र छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं भी कार्यान्वित कर रही है। अनुसूचित जाति,

अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाएं केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं जिन्हें राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। इन छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी छात्रों को लाभ प्रदान किए जाते हैं, जो उनके माता-पिता की आय की सीमा और योजना दिशानिर्देशों के अनुसार होते हैं।

वित्त वर्ष 2025-26 में, केंद्र सरकार ने पोस्ट-मैट्रिक और उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए लगभग 1.09 करोड़ छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) और विमुक्त जनजाति (डीएनटी) छात्रों के लिए लगभग 36 लाख छात्रवृत्तियां शामिल हैं; अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों के लिए लगभग 48 लाख छात्रवृत्ति; और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों के लिए लगभग 24 लाख छात्रवृत्तियां।

इस प्रकार, शिक्षा ऋण योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता के साथ-साथ विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं, उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने वाले योग्य छात्रों को व्यापक सहायता प्रदान करती हैं, यह सुनिश्चित करती हैं कि कोई भी छात्र वित्तीय बाधाओं के कारण उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के अवसर से वंचित न हो।

*****

अनुलग्नक-I

पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री तेजवीर सिंह द्वारा पूछे गए दिनांक 12/08/2026 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2767 के भाग क से ग के उत्तर में उल्लखित अनुलग्नक

राज्यवार पीएमवीएल शिक्षा ऋण डेटा (दिनांक 06.11.2024 से 03.08.2026)

क्र. सं.	छात्र का राज्य	प्राप्त आवेदनों की संख्या	छात्रों द्वारा बंद किए गए/वापस लिए गए आवेदनों की संख्या	बैंकों द्वारा अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	छात्रों/बैंकों में लंबित आवेदनों की संख्या	स्वीकृत आवेदनों की संख्या	स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)	संवितरित आवेदनों की संख्या	वितरित राशि (₹ करोड़ में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	141	47	9	9	76	10.52	66	2.87
2	आंध्र प्रदेश	14780	2800	484	1365	10131	1235.53	9144	339.71
3	अरुणाचल प्रदेश	64	25	1	8	30	6.47	26	1.02
4	असम	2787	787	143	200	1657	176.91	1458	47.69
5	बिहार	12071	3592	422	1240	6817	813.62	5860	193.94
6	चंडीगढ़	463	128	7	39	289	50.78	259	14.18
7	छत्तीसगढ	1700	322	57	158	1163	186.78	1032	48.69
8	दिल्ली	9892	2456	283	1233	5920	943.55	5279	249.18
9	गोवा	392	86	9	36	261	35.33	230	12.51
10	गुजरात	4249	866	102	342	2939	539.10	2650	144.46
11	हरियाणा	7473	1938	286	754	4495	729.89	4000	182.40
12	हिमाचल प्रदेश	1514	308	58	129	1019	101.78	867	22.14
13	जम्मू और कश्मीर	978	275	13	168	522	56.79	435	14.01
14	झारखंड	7308	1887	158	608	4655	643.50	4007	156.43
15	कर्नाटक	10576	2712	464	972	6428	758.44	5857	248.80
16	केरल	8890	1797	299	846	5948	729.62	5372	215.50
17	लद्दाख	10	2	0	1	7	0.95	6	0.20
18	लक्षद्वीप	3	2	0	0	1	0.04	0	0.00

19	मध्य प्रदेश	7937	1690	183	717	5347	845.02	4792	219.57
20	महाराष्ट्र	16890	3839	482	1518	11051	1893.19	9829	525.30
21	मणिपुर	296	107	16	29	144	13.59	119	2.80
22	मेघालय	241	52	6	23	160	15.82	142	4.14
23	मिजोरम	85	37	5	11	32	6.04	27	1.01
24	नागालैंड	121	46	3	6	66	8.44	58	1.64
25	ओडिशा	6651	1414	283	580	4374	564.21	3938	153.25
26	पुदुचेरी	335	103	9	26	197	19.48	182	6.58
27	पंजाब	3564	883	121	306	2254	347.39	1988	81.64
28	राजस्थान	8256	2027	292	655	5282	804.77	4771	194.44
29	सिक्किम	43	16	1	7	19	3.05	17	1.14
30	तमिलनाडु	19712	5321	834	1599	11958	1178.81	10879	409.43
31	तेलंगाना	7021	1692	269	561	4499	690.42	4100	179.21
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	107	23	5	14	65	9.45	58	2.43
33	त्रिपुरा	337	83	9	32	213	20.94	180	5.23
34	उत्तर प्रदेश	25492	6914	965	2647	14966	1995.06	13330	517.92
35	उत्तराखंड	3070	616	82	293	2079	256.99	1849	68.65
36	पश्चिम बंगाल	7130	1722	186	645	4577	796.44	4099	210.85
	कुल	**190579**	**46615**	**6546**	**17777**	**119641**	**16488.71**	**106906**	**4478.96**

अनुलग्नक-II

पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री तेजवीर सिंह द्वारा पूछे गए दिनांक 12.08.2026 के राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2767 के भाग क से ग के उत्तर में उल्लखित अनुलग्नक

स्वीकृत श्रेणीवार पीएमवीएल ऋण डेटा (06.11.2024 से 03.08.2026)					
क्र.सं.	**श्रेणी**	**स्वीकृत आवेदनों की संख्या**	**स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)**	**संवितरित आवेदनों की संख्या**	**वितरित राशि (₹ करोड़ में)**
1	सामान्य	68118	10361.7	61063	2983.68
2	ओबीसी	38828	4470.72	34446	1145.41
3	एससी	9693	1235.58	8683	266.81
4	एसटी	3002	420.71	2714	83.06
	कुल	**119641**	**16488.71**	**106906**	**4478.96**
	पीडब्ल्यूडी श्रेणी	604	101.42	514	16.51

ईडब्ल्यूएस के लिए स्वीकृत शिक्षा ऋणों की संख्या (06.11.2024 से 03.08.2026)			
छात्र द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार परिवार की वार्षिक आय ₹ 4.5 लाख तक है	**छात्र द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक पारिवारिक आय ₹ 4.5 से 8 लाख है**	**छात्र द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख से अधिक है**	**कुल**
61185	24900	33556	119641

अनुलग्नक-III

पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री तेजवीर सिंह द्वारा पूछे गए दिनांक 12.08.2026 के राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2767 के भाग क से ग के उत्तर में उल्लखित अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2025-26 में प्राप्त वित्त वर्ष 2024-2025 (06.11.2024 से 31.03.2025) के लिए पीएमवीएल के तहत श्रेणी-वार ब्याज छूट के लिए दावे प्राप्त हुए							
क्र.सं.	**श्रेणी**	4.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम की आय वाले परिवार के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत स्वीकृत ऋणों के लिए 100 प्रतिशत ब्याज अनुदान के लिए दावे प्राप्त हुए		8 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम की पारिवारिक आय के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत स्वीकृत ऋणों के लिए 3 प्रतिशत ब्याज छूट के लिए प्राप्त दावे		**स्वीकृत पीएम विद्यालक्ष्मी ऋणों के लिए प्राप्त कुल दावे**	
		दावों की संख्या	**निवल सब्सिडी राशि (₹ लाख में)**	दावों की संख्या	**निवल सब्सिडी राशि (₹ लाख में)**	दावों की संख्या	**निवल सब्सिडी राशि (₹ लाख में)**
1	सामान्य	2738	101.19	420	7.67	3158	108.86
2	ओबीसी	1632	54.25	231	4.07	1863	58.32
3	एससी	335	10.5	55	0.71	390	11.21
4	एसटी	111	2.71	12	0.24	123	2.95
	कुल	**4816**	168.65	**718**	12.69	**5534**	181.34

****